सच्चाई के दम पर जोश के साथ...

प्रधान संपादक: रतन प्रकाश सिंह

www.swarajindianews.com swarajindianews swarajindianews

स्वराज इंडिया

दैनिक सांध्यकालीन

कानपुर, शनिवार, 03 मई, 2025
वर्ष: 02, अंक: 127, पृष्ठ: 8+4, मूल्य: ₹ 2/-

अविवादित विरासत के मामलों का 15 दिन में हो निस्तारण

» Pg12

इनसाइड यूपीसीडा में बैकडोर से एंट्री के लिए तड़प रहे कई दागी » Pg03

चर्चा में सीओ का विवादास्पद बयान और ट्रांसफर

संभल के सिंघम को योगी सरकार ने दिया झटका

हिंसा में लगी थी गोली, बयानों ने बटोरीं सुर्खियां, खेल कोटे से भर्ती अधिकारी ने जीते कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मेडल

» प्रमुख संवाददाता, स्वराज इंडिया।

संभल। उत्तर प्रदेश के संभल में पुलिस महकमे में हुए ट्रांसफर की खबर एक बार से सुर्खियों में आ गई। संभल के सिंघम के नाम से मशहूर सीओ अनुज चौधरी का तबादला हो गया है। संभल में पिछले साल 24 नवंबर को हुई सांप्रदायिक हिंसा के बाद इस साल होली के दौरान अपने बयानों को लेकर चर्चा में आए संभल के सीओ अनुज चौधरी को संभल सर्किल से हटाकर चंदौसी सर्किल में तैनात किया गया है। हालांकि यह सर्किल भी संभल जिले का ही हिस्सा है। अब संभल सर्किल की कमान सहायक पुलिस अधीक्षक (एसपी) आलोक भाटी संभालेंगे। उन्होंने अपना चार्ज ले भी लिया है।

बीते करीब पांच-छह महीने से अनुज लगातार चर्चा में रहे। हालांकि उनके बयानों को लेकर प्रशासनिक जांच भी चल रही है। एक नजर डालते हैं उनके चर्चित बयानों पर, जो विवाद के केंद्र में आए। गौरतलब है कि सीओ अनुज चौधरी ने हिंसा के बाद एक निजी चैनल के पत्रकार से बातचीत करते हुए बयान दिया कि हम लोग मरने के लिए पुलिस में भर्ती नहीं हुए हैं। हमारे भी बीबी बच्चे हैं। कोई हमला करेगा और हम आत्मरक्षा में अपना बचाव भी नहीं करेंगे। विवादित ढांचे के सर्वे को लेकर हिंसा और बवाल हुआ था,

तब कई पुलिसकर्मियों को गोली लगी थी। इसमें संभल सीओ अनुज चौधरी भी शामिल थे। उनके पैर में गोली लगी।

होली पर जुमा वाला बयान

अनुज चौधरी मूलरूप से मुजफ्फरनगर के बहेड़ी गांव के रहने वाले हैं। अनुज चौधरी की तरफ से होली के वक्त दिया बयान देश भर में चर्चित रहा। उन्होंने कहा था कि जुमा साल में 52 बार आता है। होली साल में एक बार आती है। मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि लगता है कि होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा तो उस दिन घर से ना निकलें।

हनुमान जी की गदा लिए रैली में हुए शामिल

एक धार्मिक कार्यक्रम में हाथ में भगवान हनुमान का गदा लिए नजर आए, जिसका वीडियो वायरल हुआ था। खेलकूद कोटे से पुलिस विभाग में आए सीओ अनुज चौधरी मीडिया में अपने दो टूक बयान देने को लेकर सुर्खियों में नजर आते है। वहीं कुछ लोग उनके इस अंदाज को सिंघम मूवी का असली हीरो मानते है और सिंघम उपनाम से पुकारते है। तो वहीं कुछ लोग उनके इस अंदाज पर सोशल मीडिया पर अपत्ति भी उठाते हैं।

बॉडी और बातों में दबंगई

हालांकि सीओ अनुज चौधरी अपने बेबाक बयान पर अटल रहते हैं और सफाई में ये कहते सुने जाते हैं कि वो कोई पक्षपात बात नहीं करते हैं। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए वो सभी से अपील और कानून तोड़ने पर सख्त कार्रवाई की हिदायत भी देते है। चाहें वो किसी धर्म से हो। लोगों की अपत्ति का जबाव देते हुए उन्होंने अपने बयान में एक बार कहा था कि जिसे आपत्ति हो मेरे बयान से वो कोर्ट में जा सकते है मैंने कभी कुछ गलत नहीं कहा है।

कानून व्यवस्था दुरुस्त करने को हुआ बदलाव

बताया जा रहा है कि यह परिवर्तन कानून-व्यवस्था को और चुस्त-दुरुस्त बनाने और स्थानीय संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए किया गया है। हालांकि पुलिस महकमे की ओर से इस बारे में कोई अधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। संभल के सीओ अनुज चौधरी के अलावा भी कुछ अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। बहजोई सर्किल में तैनात रहे क्षेत्राधिकारी डॉ.प्रदीप कुमार सिह को वहां हटाकर यातायात सीओ के पद पर तैनाती दी गई है। वहीं अब तक सीओ ट्रैफिक रहे संतोष कुमार सिंह को लाइन भेजा गया है। यूपी डायल-112 का जिम्मा भी उनके पास रहेगा। इसी के साथ चंदौसी में तैनात रहे क्षेत्राधिकारी आलोक सिद्धू को बहजोई सर्किल का सीओ बनाया गया है।

खेल कोटे से पुलिस में भर्ती

अंतरराष्ट्रीय कुश्ती में भारत का मान बढ़ा चुके अनुज चौधरी खेल कोटे से उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती हुए हैं। वह अपनी लंबी चौड़ी कद काठी, फिटनेस और बेधड़क अंदाज के लिए जाने जाते हैं। अनुज चौधरी 2002 और 2010 नेशनल गेम्स में दो सिल्वर मेडल जीत चुके हैं। साथ ही एशियाई चैंपियनशिप में दो कांस्य पदक जीत चुके हैं। 1997 से 2014 तक वे कुश्ती में नेशनल चैंपियन रहे। 2001 में उनको लक्ष्मण अवॉर्ड और 2005 में अर्जुन अवॉर्ड से सम्मानित किया जा चुका है। 2012 में वह खेल कोटे से (सीओ) डिप्टी एसपी बनाए गए।

यहां बता दें कि बीते वर्ष 24 नंवबर को विवादित ढांचा जामा मस्जिद या हरिहर मंदिर सर्वे के दौरान संभल में दंगाइयों ने जमकर बवाल किया था। आगजनी और गोलीबारी भी की थी। इस हिंसा में लगभग 29 पुलिस वाले घायल हो गए थे और चार लोगों की मौत हुई थीं।

यूपी के पुलिस मुख्यालय की कपिल देव ने की तारीफ!

अखिलेश यादव बोले- हमारी सरकार में बना

» विशेष संवाददाता, स्वराज इंडिया ब्यूरो।

लखनऊ। भारत के दिग्गज आलराउंडर रहे कपिल देव ने 2 मई यानी शुक्रवार को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इसके बाद वह मीडिया से रूबरू हुए। जिसमें उन्होंने एक बयान दिया जो सुर्खियों में बना हुआ है। इसे लेकर अब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी प्रतिक्रिया देते हुए कपिल देव की सराहना की है।

दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के बाद यूपी डीजीपी प्रशांत कुमार के साथ मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने यूपी पुलिस के मुख्यालय की तारीफ की। उन्होंने कहा, मैं तो डीजीपी साहब की बड़ी तारीफ कर रहा था। कुमार साहब हद्द कर दी कि ये ऑफिस कॉरपोरेट ऑफिस से बड़ा ऑफिस लगा रहा है। इतनी अच्छी सुविधा मिलती है और क्या चाहिए। पूर्व भारतीय क्रिकेटर कपिल देव के इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर

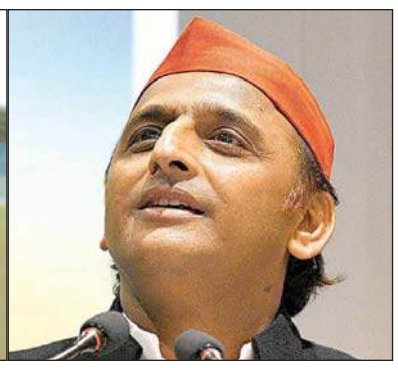

सपा प्रमुख ने प्रतिक्रिया दी है। अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा, सपा के समय लखनऊ में बने वर्ल्ड क्लास पुलिस मुख्यालय की महान क्रिकेटर कपिल देव जैसे अच्छे और सच्चे लोगों से मिली सराहना हमारा उत्साह बढ़ाती है। बड़ी सोच से प्राप्त हुई उपलब्धि का मोल और मान वही समझ सकता है, जिसने स्वयं बड़ी उपलब्धि पायी हो। भारत के दिग्गज आलराउंडर रहे कपिल देव ने 2 मई यानी शुक्रवार को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी।

इसके बाद वह मीडिया से रूबरू हुए। जिसमें उन्होंने एक बयान दिया जो सुर्खियों में बना हुआ है।

गृह विभाग की योजनाओं में भी धांधली

प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

कानपुर । शनिवार को डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने सेन पश्चिम पारा में निर्माणाधीन थाना और आवासीय परिसर के निर्माण कार्य में धांधली पकड़ी है। बिल्डिंग के पिलर तक में कमियां पाई गई। यही नहीं निर्माण कार्य इंजीनियर की बजाय मिस्त्री के भरोसे छोड़ दिया गया। कुल 25 करोड़ की योजनाओं का निर्माण किया जा रहा है।

» डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने सेन पश्चिम पारा में निर्माणाधीन थाना और आवासीय परिसर के निर्माण कार्य में धांधली पकड़ी

मिली तकनीकी खामियां और निगरानी में कमी

डीएम ने जानकारी देते हुए बताया कि निरीक्षण के दौरान स्ट्रक्चरल डिजाइन में पीडब्ल्यूडी और सीपीडब्ल्यूडी द्वारा कमियां पाई गई हैं। साइट पर कोई भी इंजीनियर नहीं मिला। निर्माण कार्य की निगरानी मिस्त्री व श्रमिकों के ऊपर छोड़ दी गई, जो मानकों के अनुरूप नहीं है।

पर्यावरण एनओसी तक नहीं ली गई

डीएम ने बताया कि 5 करोड़ रुपए लागत से अधिक की परियाजनाओं में पर्यावरण एनओसी जरूरी होती है, लेकिन वो भी नहीं ली गई। निर्माण कार्य बेहद धीमी गति से पाया गया। कई स्थानों पर बीम भी क्षतिग्रस्त पाई गई। भवन को संरचनात्मक रूप से असुरक्षित घोषित किया जा सकता है।

डीएम ने दिए कार्रवाई के निर्देश

निर्माण कार्य में कमियां मिलने पर डीएम ने निर्माण एजेंसी (यूपी कोका) के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई को कहा है। संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी सुनिश्चित की जाएगी। इसके अलावा एचबीटीयू से स्ट्रक्चर की जांच करने के निर्देश दिए हैं।

इन दो परियाजनाओं का हो रहा निर्माण

1. एक आवासीय परियोजना (लागत- लगभग 8.5 करोड़ रुपए)
2. एक अनावासीय परियोजना थाना (लागत- लगभग 17 करोड़ रुपए)

कानपुर जर्नलिस्ट क्लब के महामंत्री बोले 'देश में पत्रकारिता की भूमिका अहम'

» विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस पत्रकारों की सुरक्षा की ओर ध्यान आकर्षित करता है

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर । हर साल 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस प्रेस की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति के अधिकार और मीडिया की भूमिका को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। इस दिन को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य स्वतंत्र प्रेस की अहमियत को दर्शाना है। यह दिन पत्रकारों की सुरक्षा की ओर ध्यान आकर्षित करता है। यह दिन दुनिया भर में सूचना की आजादी और लोकतंत्र को मजबूत करने का प्रतीक है। कानपुर जर्नलिस्ट क्लब के महामंत्री अभय त्रिपाठी ने शनिवार को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मौजूदा समय में पत्रकारिता के महत्व को रेखांकित करने के साथ ही वैकल्पिक मीडिया की उभरती स्थिति पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर इस बात को खारिज नहीं किया जा सकता है कि लोकतांत्रिक देश में पत्रकारिता की अपनी एक अहम भूमिका है। मौजूदा समय में इसका पूरा स्वरूप बदल रहा है। उन्होंने कहा कि डिजिटल मीडिया के आगमन से पारंपरिक मीडिया में परिवर्तन दिखाई दे रहा है।अभय त्रिपाठी ने आगे कहा कि आने वाले दिनों में मीडिया में अनेक तरह के परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। निश्चित तौर पर इन परिवर्तनों का सामना करने के लिए हमारे पत्रकार साथियों को मानसिक रूप से तैयार रखना होगा। इसके अलावा, एआई का भी आगमन हो रहा है। इससे आने वाले दिनों में मीडिया की कार्यशैली में परिवर्तन देखने को मिल सकता है। इसके लिए पत्रकारों को खुद को तैयार रखना होगा। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में जब हमारा देश अनवरत विकास के पथ पर अग्रसर है। हम प्रतिदिन विकास के नए प्रतिमान गढ़ रहे हैं, तो ऐसे में मीडिया की भूमिका को किसी भी कीमत पर खारिज नहीं किया जा सकता है। मीडिया किसी भी राष्ट्र को नई दिशा देने में अहम भूमिका निभाता है।

विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की शुरुआत

साल 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने की शुरूआत की थी। दरअसल साल 1991 में विंडहोक सम्मेलन के बाद यूनेस्को ने इसकी सिफारिश की थी। विंडहोक घोषणापत्र में स्वतंत्र प्रेस के महत्व को रेखांकित किया गया था। तब से हर साल 03 मई को वैश्विक स्तर पर विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाने लगा।

खतरों का करना पड़ता है सामना

बता दें कि पत्रकारों को अक्सर धमकियों, हमलों, सेंसरशिप और झूठे मुकदमों का सामना करना पड़ता है। कई बार पत्रकारों को जान से मारने की धमकी मिलती है। कई बार उनकी हत्या तक कर दी जाती है। ताकतवर समूह और सरकारें पत्रकारों की आवाज को दबाने का प्रयास करते हैं।

यूपीसीडा में बैकडोर से इंट्री के लिए तड़प रहे कई 'दागी'

प्रमुख संवाददाता, स्वराज इंडिया

कानपुर। उप्र औद्योगिक विकास प्राधिकरण(यूपीसीडा) में कई दागी एवं भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारी रिटायर होने के बाद बैकडोर से विभाग में इंट्री के लिए तडप रहे हैं। सूत्र कह रहे हैं यूपीसीडा को उनकी जरूरत भले ही उतनी न हो लेकिन वह यूपीसीडा के बिना नहीं 'जी' पा रहे हैं! बताया जाता है कि वह इसलिए आना चाहते हैं कि नौकरी के दौरान किए गए घपले-घोटालों को बराबर कर सकें और फिर से खुलकर खेल कर सकें। इसके लिए आउटसोर्सिंग के अलावा अन्य नियमावली को आधार बनाकर विभाग में फिर से काम करने के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अब देखना यह है कि तेज तर्रार सीईओ मयूर माहेश्वरी इसपर कितना नियंत्रण लगा पाते हैं।

» **रिटायर होने के बाद कई अधिकारी और कर्मचारी फिर से काम करना चाहते हैं**

» **यूपीसीडा में स्थाई सेवा के दौरान लग चुके हैं गंभीर आरोप**

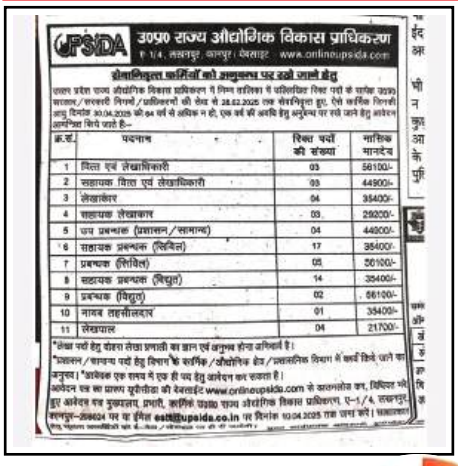

उ0प्र0 राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण
www.onlineupsida.com

क्र.सं.	पदनाम	रिक्त पदों की संख्या	मासिक मानदेय
1	वित्त एवं लेखाधिकारी	03	56100/-
2	सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी	03	44900/-
3	लेखाकार	04	35400/-
4	सहायक लेखाकार	03	29200/-
5	उप प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)	04	44900/-
6	सहायक प्रबन्धक (सिविल)	17	35400/-
7	प्रबन्धक (सिविल)	05	56100/-
8	सहायक प्रबन्धक (विद्युत)	14	35400/-
9	प्रबन्धक (विद्युत)	02	56100/-
10	नायब तहसीलदार	01	35400/-
11	लेखपाल	04	21700/-

यूपी के कई सरकारी विभागों में अधिकारियों एवं कर्मचारियों की कमी को देखते हुए योगी सरकार ने रिटायर हो चुके कर्मियों को पुनः न्यूनतम मानदेय पर रखने के निर्देश दिए थे, इसके बाद विभागों में ऐसे कर्मियों का मेडिकल एवं सेवाभाव को देखकर रखा जा रहा है। वहीं, यूपीसीडा में कुछ ऐसे कार्मिक हैं जो कि विभाग में इंट्री के लिए तडप रहे हैं। इनमें एक नाम है अहमद अली का जो कि उपप्रबंधक सामान्य पद से रिटायर हो चुके हैं। वहीं दूसरा नाम है सतीश गुप्ता का जो कि वित्त एवं लेखाधिकारी पद से रिटायर हो चुके हैं साथ ही एक लेखाकार का भी नाम बताया गया है। कुछ और भी नाम है जो कि फिर से विभाग में काम करने के लिए पैरवी कर रहे हैं। इन लोगों ने नौकरी के दौरान विभाग में जमकर अनियमितताएं करके यूपीसीडा को चूना लगाया। कई भूखंडों में जमकर खेल किया। कई शिकायतें भी हुई लेकिन अधिकारियों से सेटिंग के दमपर दबा दी गई। इन लोगों ने इंट्री के लिए आवेदन किया था लेकिन निरस्त कर दिया गया।

सूत्रों का दावा है कि यह लगातार विभाग में बैकडोर से इंट्री के लिए जोर अजमाइश कर रहे हैं। हालांकि, सीईओ मयूर माहेश्वरी के पास मामला संज्ञान में है, वह सख्त एक्शन के लिए जाने जाते हैं, उन्होने यूपीसीडा की कार्यशैली में बदलाव के लिए कई प्रयास किए हैं। सीईओ से कई बार अधिकारियों ने गुमराह करके गलत फैसले कराए जिससे सवाल भी उठ चुके हैं।

खास खबर

विभाग में बिना सेलरी वाले कर्मियों का बोलबाला....

यूपीसीडा में कई अधिकारियों ने अपने खास लोगों को बिना सेलरी के लगा रखा है। यह लोग अकाउंट एवं इंजीनियरिंग में जमे हुए हैं। यही लोग दो नंबर के पैसा का हिसाब रखते हैं और शाम को अधिकारियों के घर तक पहुंचाते हैं। यह कर्मचारी आउटसोर्सिंग में भी नहीं हैं। ऐसे में विभाग की गोपनीयता भंग होने का पूरा खतरा हमेशा रहता है। सूत्रों का दावा है कि ऐसे करीब एक दर्जन लोग होंगे जो कि विभिन्न कार्यालयों में काम कर रहे हैं।

निजीकरण के विरोध में बिजली कर्मचारियों ने निकाली बाइक रैली

संविदा कर्मियों की बहाली व स्मार्ट मीटर लगाने का आदेश वापस लेने की मांग

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर। केस्को और कानपुर जोन के बिजली कर्मचारियों व अभियंताओं ने बिजलीघर गेट से फूलबाग गांधी प्रतिमा तक बाइक रैली निकालकर निजीकरण का विरोध किया। निजीकरण से होने वाले नुकसान भी बताये। हटाये गए संविदा कर्मियों को बहाल किये जाने और कर्मचारियों के घरों पर स्मार्ट मीटर लगाए जाने के आदेश को वापस लिए जाने की मांग की। संघर्ष समिति ने कहा कि निजीकरण की दृष्टि से बड़े पैमाने पर सभी विद्युत वितरण निगमों से संविदा कर्मियों को हटाए जाने का आदेश तत्काल वापस लिया जाए। एक मई से बिजली कर्मियों ने आंदोलन शुरू कर दिया है। आंदोलन के अगले चरण में दो मई से सात दिन तक लखनऊ स्थित शक्ति भवन पर क्रमिक अनशन किया जाएगा। पदाधिकारियों ने कहा कि संघर्ष समिति के साथ 5 अप्रैल 2018 और 6 अक्टूबर 2020 को दो समझौते हुए हैं, जिसमें स्पष्ट लिखा है कि बिजली कर्मियों को विश्वास में लिए बिना ऊर्जा क्षेत्र में कोई निजीकरण नहीं किया जाएगा। 42 जनपदों के विद्युत वितरण का किया जा रहा निजीकरण इन दोनों समझौते का स्पष्ट उल्लंघन है।

कानपुर में अतिक्रमण के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक जारी

» मेयर प्रमिला पांडेय और नगर आयुक्त सुधीर कुमार के निर्देश पर पूरे शहर में चल रहा अभियान

» सबसे पहले नाले और नालियों से अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर। महापौर एवं नगर आयुक्त सुधीर कुमार द्वारा शहर की जनमानस को जल भराव व जाम इत्यादि की समस्याओं से निजात दिलाए जाने हेतु चलाए जा रहे संयुक्त अतिक्रमण अभियान के अंतर्गत कार्यवाही जारी है। नगर आयुक्त सुधीर कुमार द्वारा समस्त जोनल अधिकारियों को निर्देश दिए गए की जिन-जिन स्थानों से अतिक्रमण हटाकर स्थल को जनमानस हेतु सुगम बनाया गया है , वहां यह सुनिश्चित करें कि किसी भी दशा में पुनः अतिक्रमण न हो पाए।

जोन1–02.05.2025 को जोन–1 सीमान्तर्गत कलक्टरगंज माल गोदाम रोड पर भवन संख्या 73/9 से 73/14 तक स्वास्थ्य विभाग के नाले के ऊपर से अतिक्रमण अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान नाले के ऊपर से 3 झोपड़ी, लगभग 10 पक्की रैम्प, लगभग 20 ठेले / अस्थाई अतिक्रमण हटवाये गये तथा 2 ट्रक मलबा उठवाया गया। अभियान के दौरान जोनल अधिकारी जोन–1, जोनल अभियंता जोन–1, जोनल स्वच्छता अधिकारी जोन–1, कर अधीक्षक जोन–1, क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक व नगर निगम की क्यू0आर0टी0 टीम उपस्थित रही।

जोन–2– क्षेत्रान्तर्गत हंस मंन्दिर सतबरी रोड से नीलकण्ठ साड़ी वाले तक नाला सफाई किये कुछ रैम्प व जीनों को ध्वस्त किया गया व स्थल की सफाई भी सुनिश्चित करायी गयी ।अभियान वो दौरान लगभग रु.10,000/– का जुर्माना वसूला गया।

जोन–5– पनकी क्षेत्र में स्वराज नगर में सी0–192 से चन्देल मार्ग से थाना पनकी होते हुये बी0एम0सी0 हॉस्पिटल तक अतिक्रमण हटाया गया। चिन्हित स्थल पर लगभग 40–45 अस्थायी अतिक्रमण एवं 15–20 स्थलों पर हुये स्थायी अतिक्रमण को हटाया गया, जिसमें नाले पर बने जाने हेतु अभियान चलाया गया। नाला सफाई एवं अतिक्रमण अभियान के दौरान 25 टीन सेड, फुटपाथ से 15 चतबूतरे हटाये गये एवं जुर्माना सं0 4000/–वसूला गया है। उक्त अभियान के दौरान अभियन्त्रण विभाग एवं प्रवर्तन दल मौजूद रहा।

सम्पादकीय

रॉक गार्डन पर अदूरदर्शितापूर्ण फैसला

कला के संरक्षण के लिये नीति-नियंताओं से संवेदनशील व्यवहार की उम्मीद की जाती है। बहुत संभव है कि यह संरक्षण दैनिक जीवन में किसी तरह की विसंगति पैदा करे, लेकिन भावी पीढ़ियों को अतीत के कला सौंदर्य से रूबरू कराना हर समाज का दायित्व होता है। कला संरक्षण की प्रासंगिकता का प्रश्न पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय के उस निर्देश के बाद फिर सामने उत्पन्न हुआ है, जिसमें सड़क को चौड़ा करने तथा पार्किंग के विस्तार के लिये रॉक गार्डन की दीवार के एक हिस्से को ध्वस्त करने का निर्देश दिया गया है। यह प्रकरण विरासत के संरक्षण और बुनियादी ढांचे के विस्तार के बीच संतुलन को लेकर गंभीर चिंता उत्पन्न करता है। निस्संदेह, केंद्र शासित प्रदेश के अधिकारियों द्वारा क्रियान्वित निर्णय न केवल रॉक गार्डन के निर्माता नेक चंद की कलात्मक विरासत के एक हिस्से को मिटा देता है, बल्कि एक परेशान करने वाली मिसाल भी स्थापित करता है। जो बताता है कि कि नया भारत विकास के नाम पर अपनी सांस्कृतिक व वन विरासत के साथ कैसा व्यवहार करता है। निस्संदेह, इस तथ्य को लेकर दो राय नहीं हो सकती है कि रॉक गार्डन ने केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ को एक विशिष्ट पहचान दी है। नेकचंद की इस विरासत ने दुनिया को बेकार और अनुपयोगी चीजों को नया स्वरूप देने की एक नई दृष्टि प्रदान की है। दशकों से रॉक गार्डन रचनात्मक मानवीय कला दृष्टि के प्रमाण के रूप में खड़ा है कि कैसे सकारात्मक सोच के साथ कचरे को आश्चर्यजनक कृति में तब्दील किया जा सकता है। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि नेकचंद की इस अद्भुत कला से प्रेरित होकर देश-दुनिया के विभिन्न भागों में रॉक गार्डन की प्रतिकृति बनाने की भी प्रेरणा भी मिली। नेकचंद के जाने के बाद भी रॉक गार्डन कलात्मकता के एक जीवंत प्रमाण के रूप में विद्यमान है। ऐसे में समाज व प्रशासन का नैतिक दायित्व बनता है कि इस सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण किया जाए।यही वजह है कि सिटी ब्यूटीफुल के तमाम जिम्मेदार, सजग व संभ्रांत लोग अपनी सांस्कृतिक विरासत की रक्षा के लिये आगे आए हैं। यह विडंबना कही जाएगी हम अपनी समृद्ध और कलात्मक विरासत के एक हिस्से को सड़क निर्माण और प्रदूषण बढ़ाने वाले वाहनों के उपयोग के लिये बनायी जा रही पार्किंग के लिये खो देंगे। यह भी तर्क दिया जा रहा है कि ध्वस्त की गई दीवार रॉक गार्डन में नेक चंद द्वारा बनायी गई मूल संरचना का हिस्सा नहीं थी। यदि यह तर्क स्वीकार भी कर लिया जाता है तो भविष्य में इस दलील के आधार पर इसके अन्य हिस्सों के अस्तित्व पर संकट मंडरा सकता है। निस्संदेह, किसी संरचना या सांस्कृतिक प्रतीक के महत्व को उसके ढांचे के रूप में नहीं बल्कि उसके साथ लोगों के सांस्कृतिक और भावनात्मक जुड़ाव के रूप में देखा जाना चाहिए।

उनकी भी सोचें जिनसे किसी ने हमदर्दी नहीं जतायी

गुरबचन जगत

पंजाब से युवाओं के पश्चिमी देशों की ओर पलायन की कई लहर चलीं। बेहतर भविष्य की तलाश में वे विदेश गये क्योंकि यहां रोजगार के माकूल अवसर नहीं। ऐसे में वैध-अवैध पलायन जारी रहा। अमेरिका का इन लोगों को बेड़ियों में जकड़ना कुछ ज्यादा ही आसान रहा लेकिन देश में विदेशी मुद्रा लाने वाले इन अप्रवासियों का अपमानजनक निर्वासन और उस पर देश में कोई प्रतिक्रिया व्यक्त न करना चिंताजनक है।पंजाब– पांच दरियाओं की धरती,यूनानी जिसे पेंटापोटामिया (इसका अर्थ भी वही है) पुकारते थे। वह धरा जो प्राचीन काल में सिंधु घाटी सभ्यता, ऋग्वेद और महाभारत की रही। इसी भूमि पर सिकंदर ने झेलम के तट पर पोरस से युद्ध किया, बाबर ने इब्राहिम लोदी से युद्ध किया, एंग्लो-सिख युद्ध यहीं लड़े गए - पंजाब जैसी भूमि के उदाहरण कम ही हैं, जिसने सदियों तक आक्रमण, तबाही और लूटपाट झेली हो।

हम शुरुआत करते हैं 1947 के बाद से, यानी वह घड़ी जो एक शानदार युग की सुबह होने वाली थी। यह प्रभात शेष भारत में खुशी और धूप की तरह खिली, सिवाय पंजाब और बंगाल सूबों के। जो विभाजन हुआ, वह काफी हद तक पंजाब और बंगाल का था। अंग्रेजों द्वारा खींची गई और कांग्रेस नेतृत्व , गांधी और जिन्ना द्वारा स्वीकार की गई एक काल्पनिक रेखा ने पंजाब को बांट दिया। यह पंजाब के शरीर और आत्मा के टुकड़े करना था। इसने अपने पीछे हत्या, बलात्कार और तबाही की सुनामी छोड़ी। ऐसा रक्तपात पहले कभी नहीं हुआ और संभवतः इतिहास का विशालतम जबरन पलायन।यह बड़ी उथल-पुथल कदाचित 1950 के दशक के शुरू में पश्चिमी दुनिया की ओर शुरू पलायन की पहली लहर के अंतर्निहित मुख्य कारणों में से एक थी। शुरू में, यह मामूली थी, अधिकांशतः यूके और उसके बाद कनाडा की तरफ। दो विश्व युद्धों में इस इलाके का योगदान बहुत बड़ा था, और लौटकर आए फौजी यूरोप, अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और मध्य पूर्व से कहानियां व अनुभव सुनाते थे। मनुष्य सदा बेहतर जिंदगी तलाशता रहा, और जब घर पर मौके निराशाजनक हों, तो वह बाहर की ओर देखता है।

यहां देश में, पंजाबी जीवट धीरे-धीरे तारी हुई और अच्छे नेतृत्व और प्रशासन की मदद से, हमने बिखरे टुकड़े सहेजे और विभाजन की भयावहता पर काबू पाया और लगभग सामान्य जीवन जीने लगे। कुछ दशकों तक लगा कि हम समृद्धि-शांति की राह पर हैं। परंतु यह मृगतृष्णा साबित हुई और राजनीतिक-प्रशासनिक व्यवस्था में खामियां उभरने लगीं। पहले से बंटे पंजाब में और विभाजन की मांग की गई जो अंततः सफल हुई। अकाली सिख वर्चस्व वाला राज्य चाहते थे, वहीं पहाड़ी लोगों ने अपने लिए सुरक्षित सूबा मांगा, ठीक यही हरियाणा के लोगों ने किया। संयुक्त पंजाब को तीन राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया। चंडीगढ़, जिसे लाहौर के स्थान पर बतौर आधुनिक राजधानी विकसित किया गया था, वह भी जाती रही।विभाजन से पूर्व के पंजाब सूबे के पांच प्रशासनिक संभाग थे – जलंधर (अब जालंधर), लाहौर, दिल्ली, मुल्तान और रावलपिंडी। इसे बड़ी उपलब्धि के रूप में सराहा गया, लेकिन असल में इसने पंजाब के पतन की शुरुआत की क्योंकि लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था और पतनशील नेतृत्व ने अफरातफरी पैदा की। पहाड़ और उनके जंगल व जलीय स्रोत हिमाचल में वहीं राष्ट्रीय राजधानी की निकटता, इसके फायदे और यमुना किनारे की भूमि हरियाणा में चले गए। इस क्षेत्र का नाम बदलकर अब 'लघु आब' कर दिया जाना चाहिए क्योंकि यह अब 'पंज-आब' कहलवाने लायक नहीं रहा।

खतरे में है कश्मीर की नैसर्गिक अस्मिता

मौसम की मार

पंकज चतुर्वेदी

सेब की अच्छी फसल के लिए चालीस दिन के लिए कड़ाके की ठंड अनिवार्य होती है जो इस बार दिखी नहीं। कुछ साल पहले तक कश्मीर में सालाना 20 से 25 लाख मीट्रिक टन से अधिक सेब की पैदावार होती थी, अब यह घट कर केवल 17-18 लाख मीट्रिक टन रह गई है।

बीते कुछ सालों में कश्मीर घाटी के मौसम में बदलाव यहां के नैसर्गिक पर्यावरण के अस्तित्व के लिए खतरा बन गया है। आमतौर पर 21 दिसंबर से 29 जनवरी तक कश्मीर घाटी में चिलई कलां के दौरान तापमान शून्य से नीचे और भारी बर्फबारी होती है। मौसम विज्ञानियों ने भविष्यवाणी की थी कि 2024-2025 में ला नीना प्रभाव के कारण इस क्षेत्र में अच्छी बरसात होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं।

न बर्फ गिरी और न ही बरसात। मौसम विभाग ने पहले ही कश्मीर घाटी में जनवरी के महीने में 81 प्रतिशत कम बारिश होने के चलते अलर्ट जारी किया है। कठुआ में पिछले करीब तीन माह के दौरान क्षेत्र में इस बार पर्याप्त वर्षा न होने के कारण किसानों की फसलें सूखने के कगार पर आ गई हैं।सर्दियों में गर्मी का खेती-किसानी पर असर कई तरीके से हो रहा है। तापमान बढ़ने से कीटों की सुप्तावस्था जल्दी समाप्त हो जाती है, जिससे उनके संक्रमण चक्र बढ़ जाते हैं। जब फल के पेड़ों पर फूल आते हैं, तभी कीट का प्रकोप बढ़ने

पर कीट नियंत्रण अधिक कठिन हो जाता है। पुष्पावस्था में कीटनाशकों का छिड़काव उपज और गुणवत्ता दोनों को प्रभावित करता है। सेब फल के पत्तों को खाने वाले कीट सक्रिय हो जाते हैं। इसके अलावा पत्ता गोभी सहित अधिकांश सब्जियों के पौधों पर कीट हमला कर रहे हैं। उच्च तापमान से कुछ ऐसे एंजाइमों का उत्पादन होता है जो समशीतोष्ण फलों के पेड़ों के लिए हानिकारक होते हैं।आलूबुखारा, खुबानी, चेरी, नाशपाती और यहां तक कि सेब जैसी बागवानी फसलों पर जल्दी फूल लगने से उनका उत्पादन चक्र गड़बड़ा रहा है और अनुकूल मौसम न होने के कारण या तो फूल फल में परिवर्तित नहीं हो पा रहे या फिर बहुत कमजोर हो रहे हैं। तापमान का असर मधुमक्खी और भंवरे जैसे कीटों पर भी पड़ा है, जिससे परागण की नैसर्गिक प्रक्रिया प्रभावित हुई है। वैसे भी सेब की अच्छी फसल के लिए चालीस दिन के लिए कड़ाके की ठंड अनिवार्य होती है जो इस बार दिखी नहीं। कुछ साल पहले तक कश्मीर में सालाना 20 से 25 लाख मीट्रिक टन से अधिक सेब की पैदावार होती थी, अब यह घट कर केवल 17-18 लाख मीट्रिक टन रह गई है। जलवायु परिवर्तन से सर्वाधिक प्रभावित हुई है केसर की खेती। बेमौसम गर्मी के कारण न तो उसकी जड़ों का विस्तार हो पा रहा है और न ही पौधे की वृद्धि।

कम बर्फबारी का सबसे दूरगामी कुप्रभाव है यहां की जल निधियों का अभी से सूखना। गांदरबल जिले की कई सरिताएं और छोटी नदियां अब सूख चुकी हैं। अनंतनाग जिले के मशहूर अचाबल तालाब में तली दिख रही है। कभी इससे 15 गांवों को पानी की आपूर्ति और कई सौ एकड़ धान के खेतों की सिंचाई होती थी। अनंतनाग जिले में वेरीनाग स्रोत में पानी का बहाव बहुत कम हो गया है। वेरीनाग से झेलम नदी निकलती है, जो घाटी के बीच से अनंतनाग, पुलवामा, श्रीनगर, गांदरबल, बांदीपोरा और बारामूला जिलों तक बहती है और फिर पाकिस्तान के मिथनकोट में सिंधु नदी में मिल जाती है।

न घोड़ी न बैंडबाजा, न ही लिया दहेज

इंजीनियर दूल्हे ने बैलगाड़ी पर निकाली बारात, लोग हैरान

» विशेष संवाददाता, स्वराज इंडिया ब्यूरो।

दुल्हन भी हुई इम्प्रेस

झांसी। आधुनिकता के युग में आधुनिक संसाधनों का उपयोग करना मानव जीवन की शैली में शामिल है परंतु इस युग में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो पुरानी परम्पराओं को आज भी कायम रखे हैं। दुल्हन की ऐसी विदाई देख लोग अचंभित रह गए। इंजीनियर दूल्हा अपनी शिक्षिका दुल्हन को बैलगाड़ी से विदा कराकर ले गया।

मामला बुधवार (30 अप्रैल) की सुबह का है। झांसी के वीरांगना नगर के एक विवाह घर में 29 अप्रैल (मंगलवार) को एक विवाह कार्यक्रम था। चिरगांव के ग्राम जरयाई निवासी संतोष कुमार विश्वकर्मा के बेटे इंजीनियर अभिजीत का विवाह मध्य प्रदेश के जिला अशोकनगर के ग्राम मुनावली निवासी शिक्षक रामगोपाल विश्वकर्मा की शिक्षिका पुत्री बबली विश्वकर्मा से हुई।

बबली मध्य प्रदेश के एक सरकारी विद्यालय में कार्यरत हैं। बुधवार की सुबह जब विदाई समारोह हुआ तो उनकी विदा कार या किसी हेलीकॉप्टर से नहीं, पुरानी परंपराओं के अनुसार बैलगाड़ी से हुई। सबसे खास बात यह रही की दूल्हे के पिता संतोष कुमार ने बताया कि उन्होंने अपने बेटे का विवाह बिना दान-दहेज के किया है। संतोष इस बात से चिंतित दिखे कि भारतीय परम्परा नष्ट हो रही है।

भारतीय संस्कृति में किसान को देवता माना जाता था। यह कृषि प्रधान देश है तो संसाधनों का सम्मान भी होना चाहिए। इसी सोच के साथ उन्होंने जब अपने परिवार के समक्ष दुल्हन की विदायी का प्रस्ताव बैलगाड़ी से कराने का रखा, तो सभी ने इसे मान लिया।

अवैध रिश्ते ने परिवार को कर दिया पूरी तरह बर्बाद

नाबालिग छात्र से अवैध रिश्ता, पति का मर्डर

पामेला ने सुनाई अलग कहानी

पामेला ने हमेशा अपनी बेगुनाही का दावा किया। उसने कहा कि फ्लिन ने बदला लेने के लिए ऐसा किया क्योंकि वह उसके साथ रिश्ता खत्म कर रही थी। पामेला ने बताया कि वो फिर से अपनी शादीशुदा जिंदगी की तरफ लौट रही थी। उसने उन सभी आरोपों को भी गलत बताया, जिनमें कहा गया कि तलाक से बचने और 1 लाख 40 हजार रुपये की बीमा रकम पाने के लिए पामेला ने ये सब किया।

रहस्यमयी कहानी

अनूप अवस्थी

» आज भी जेल में है पामेला, खुद को बताती है बेकसूर

» कोर्ट में सारी गवाही हुई पामेला के खिलाफ।

नई दिल्ली। 1990 के दशक की एक ऐसी वारदात, जिसमें एक हंसता-खेलता परिवार पूरी तरह उजड़ गया। वो 1 मई 1990 का दिन था, जब न्यू हैंपशायर में रहने वाले 24 वर्षीय ग्रेग स्मार्ट की लाश उनके घर में मिली। कातिल ने उनके सिर में सटाकर गोली मारी थी। मामले की तफ्तीश शुरू हुई तो शक की सुई ग्रेग की 22 साल की पत्नी पामेला स्मार्ट पर गई। धीरे-धीरे राज खुलने लगे और फिर सामने आई अपने नाबालिग छात्र के साथ पामेला के अवैध रिश्ते और कत्ल की खौफनाक कहानी।

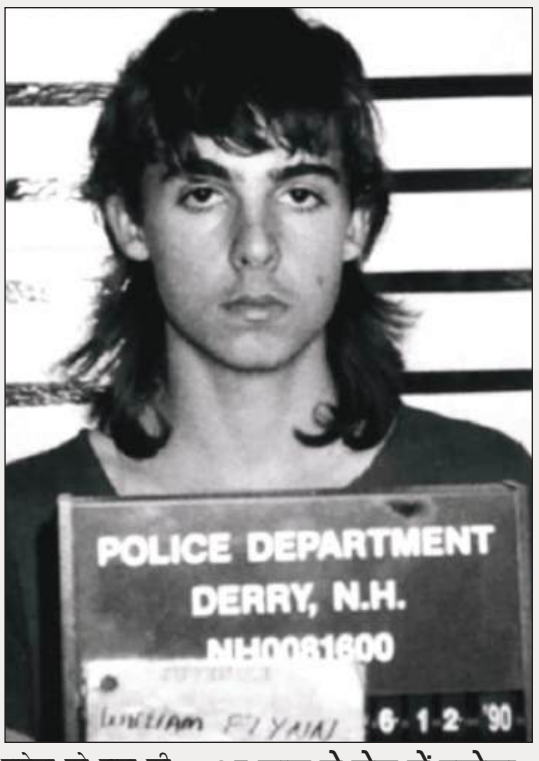

कहानी की शुरुआत हुई 39 साल पहले, जब पामेला अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही थी। 1986 में एक म्यूजिक इवेंट के दौरान उसकी मुलाकात ग्रेग से हुई और दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया। पामेला के ग्रेजुएशन फाइनल ईयर के दौरान दोनों फ्लोरिडा में साथ रहे और इसके बाद न्यू हैंपशायर वापस चले गए। दोनों ने यहां एक घर खरीदा और 1989 में शादी कर ली। ग्रेग एक बीमा एजेंट के तौर पर काम करते थे और पामेला पास के ही एक स्कूल में मीडिया कोऑर्डिनेटर थीं। दोनों की जिंदगी में सबकुछ ठीक चल रहा था लेकिन कुछ वक्त बाद हालात बदल गए। 1 मई 1990 को ग्रेग की खून से लथपथ लाश उनके घर में मिली। उनके सिर में गोली मारी गई थी। पामेला ने पुलिस को बताया कि किसी ड्रग एडिक्ट ने रकम लेने के लिए उन्हें गोली मारी होगी।

पामेला के कहने पर चलाई मैंने गोली: बिली फ्लिन

तहकीकात हुई तो पुलिस को पता चला कि पामेला के अवैध संबंध अपने एक नाबालिग छात्र विलियम बिली फ्लिन से हैं। पुलिस ने फ्लिन और पामेला को गिरफ्तार किया और मामले की सुनवाई कोर्ट में शुरू हो गई। सुनवाई के दौरान फ्लिन ने बयान दिया कि उसने ही गोली मारी थी, लेकिन यह भी कहा कि उसने यह सब पामेला के कहने पर किया था। अपने बयान में उसने कहा कि पामेला को डर था कि तलाक होने पर वह सब कुछ खो देगी

वहीं, पामेला ने अपने ऊपर लगे इस आरोप को नकार दिया और कहा कि उसने कभी भी फ्लिन को अपने पति को मारने के लिए नहीं कहा। पुलिस ने कोर्ट में कहा कि इस हत्याकांड में फ्लिन के कुछ और दोस्तों ने भी साथ दिया। इन सभी लोगों ने पामेला के खिलाफ गवाही दी। सुनवाई पूरी हुई और 1991 में पामेला को हत्या की साजिश रचने और दो अन्य अपराधों का दोषी पाया गया।

न्यूज वेबसाइट पीपुल के मुताबिक, सजा मिलने के बाद एक इंटरव्यू में पामेला ने स्वीकार किया कि फ्लिन के साथ उसके अवैध संबंध गलत थे और उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जो कुछ हुआ, वह इसके लिए खुद को लगातार सजा दे रही है। उसने कहा, मुझे लगता है कि भले ही मैंने उसे ग्रेग को मारने के लिए नहीं कहा और भले ही मैंने उसे बंदूक नहीं दी, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने इस रिश्ते को रखकर उस बंदूक में गोलियां डाल दीं।

35 साल से जेल में पामेला, नहीं मिली रिहाई

पामेला 1990 में अपनी गिरफ्तारी के बाद से सलाखों के पीछे है और दशकों से अपनी सजा के खिलाफ अपील करने की कोशिश कर रही हैं। जेल में रहते हुए पामेला ने मंत्रालय में डॉक्टरेट की डिग्री और तीन मास्टर डिग्री हासिल की। इसके बाद उन्होंने अपने साथी कैदियों को भी पढ़ाया। हालांकि, साल 2021 की अपील में पामेला ने ग्रेग की मौत की जिम्मेदारी ली और उनके परिवार से माफी मांगी। उन्होंने कहा, हां मैं दोषी हूं। हालांकि, पामेला को रिहाई नहीं मिली।

बिना जन्म प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा सरकारी स्कूलों में एडमिशन!

- सरकार के नए आदेश से अभिभावको की नींद उड़ी
- स्कूल और अफसरों के चक्कर लगाने को मजबूर अभिभावक
- आरटीई की खुले आम धज्जियां उड़ा रहे हैं जिले में अफसर
- राजनैतिक दल मान रहे वंचितों को शिक्षा से दूर रखने की साजिश

स्वराज इंडिया ब्यूरो

कानपुर। नई शिक्षा नीति के बाद शासन से जारी किए गए जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर प्रवेश लेने के तुगलकी फरमान ने पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों के लिए प्राथमिक शिक्षा के रास्ते लगभग बंद कर दिए हैं। यही वजह है कि सरकारी स्कूलों में प्रवेश के लिए अभिभावक चक्कर लगा रहे हैं और स्कूलों के हेड मास्टर उन्हें नियम कानून बताकर टरका रहे हैं। ऐसे में पूरे प्रदेश के परिषदीय स्कूलों में नवीन नामांकन का स्तर पिछले वर्षों की अपेक्षा बहुत नीचे गिर गया है।

गौरतलब है कि नई शिक्षा नीति में आयु के अनुसार उसके अनुरूप कक्षा में प्रवेश दिए जाने का प्रावधान किया गया है। ग्रामीण और शहरी परिवेश में ऐसे कई बच्चे हैं। जिनके माता पिता ने जन्म के समय जन्म प्रमाण पत्र जारी करवाने में कोई दिलचस्पी नहीं ली। अब उनके पास बच्चे के जन्म का कोई प्रमाण भी नहीं है। आम तौर पर आज भी गांवों में गरीब घरों की महिलाओं का प्रसव घरों पर ही कराया जाता है। ऐसे में वह अस्पताल तक नहीं पहुंच पाती हैं। कुछ जागरूक महिलाएं सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के चक्कर में अस्पताल तक पहुंचती हैं लेकिन वहां से मिले कागजात लंबे समय तक सुरक्षित रख पाना उनके लिए बहुत मुश्किल काम होता है।

लेकिन एसडीएम ने जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए अस्पताल अथवा टीकाकरण का कोई सरकारी अभिलेख होना अनिवार्य कर दिया है। जिससे 6 वर्ष की आयु पूरी कर चुके सैकड़ों बच्चे सरकारी स्कूलों में दाखिले से वंचित रह गए हैं। वह स्कूलों और अफसरों के चक्कर लगा रहे हैं लेकिन उन्हें कहीं से संतोषजनक जवाब नहीं मिल पा रहा है।

जबकि शिक्षा का अधिकार कानून में 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बच्चे को बुनियादी शिक्षा हासिल करने का अधिकार दिया गया है। लेकिन विभागीय अफसर अपने ही बनाए कानूनों को शायद भूल गए हैं। वहीं बीते वर्षों में बिना आधार के एडमिशन लेने वाले प्रधानाध्यापक काफी झमेले में फंस गए थे। कई बच्चों की डीबीटी रकम भी नहीं आई थी। वह अबकी बार किसी सरदर्द से बचने के ऐसे एडमिशन करने से बच रहे हैं। हालांकि बीएसए एक आदेश भी जारी कर चुके हैं जिसमें कहा गया है कि प्रवेश के लिए आधार की अनिवार्यता नहीं है। वहीं आधार बनवाने के लिए जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य है। इसे सब क्यों भूल जाते हैं।

छह महीने पहले जमा प्रार्थना पत्रों पर कोई कार्रवाई नहीं

बिल्हौर। करीब छह महीने पहले परिषदीय स्कूलों के बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र और उसके आधार पर आधार बनवाने के लिए विभागीय स्तर पर पहल की गई थी। जिसमें शिक्षकों को बच्चों के अभिभावकों के प्रार्थना पत्र इकट्ठा करके बीआरसी में जमा करने को कहा गया था। बाद में यहां से वे एसडीएम के यहां भेज दिए जाते थे। आलम यह है कि शुरुआत में ऐसे कुछ प्रमाण पत्र जारी हो गए लेकिन कई प्रार्थना पत्रों पर छह महीने बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है।

पीडीए वर्ग को शिक्षा से वंचित करने की साजिश रच रही भाजपा- विनय यादव

बिल्हौर। समाजवादी पार्टी के बिल्हौर विधानसभा अध्यक्ष विनय सिंह यादव ने कहा कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले करीब 80 फीसदी बच्चे दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं।

जिनके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है। ऐसा लगता है कि लंबे लंबे दावे करने वाली प्रदेश की भाजपा सरकार ने ऐसे बच्चों को शिक्षा के बुनियादी अधिकार से वंचित करने के लिए ही अफसरों से मिलीभगत करके ऐसे आदेश दिए हैं। जिससे इस वर्ग के लोग पढ़ लिखकर समाज की मुख्यधारा में न आ सकें। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के सामने रखा जाएगा। ताकि ऐसे बच्चों को शिक्षा के अधिकार से वंचित न होना पड़े।

कहीं डीबीटी की धनराशि हजम करने के लिए तो नहीं जारी किया गया आदेश- रचना सिंह

बिल्हौर। परिषदीय स्कूलों के प्रत्येक बच्चे के लिए आधार सत्यापन के बाद प्रति वर्ष सरकार डीबीटी के जरिए अभिभावकों के खातों में 1200 रुपए सीधे भेजती है। जिससे उनकी ड्रेस और जूते मोजों का इंतजाम हो सके। लेकिन अधिकांश बच्चे पूरे साल बिना ड्रेस के दिखते हैं। बताया जाता है कि अभिभावक यह पैसा अपने ऊपर खर्च कर डालते हैं।पहले स्कूलों के माध्यम से यह व्यवस्था की जाती थी। जिससे ही बच्चे को ड्रेस मिल जाती थी। बिल्हौर विधानसभा से प्रत्याशी रही रचना गौतम ने आशंका जताई है कि कहीं सरकार ने यह धनराशि देने से बचने के लिए नामांकन कम करने का कोई आसान तरीका तो नहीं ढूंढ लिया है। उन्होंने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी गरीबों को शिक्षा की वकालत करते थे और यह सरकार उनकी मंशा पर पानी फेर रही है। जिसका खामियाजा अबकी चुनाव में भाजपा सरकार को भुगतना ही पड़ेगा।

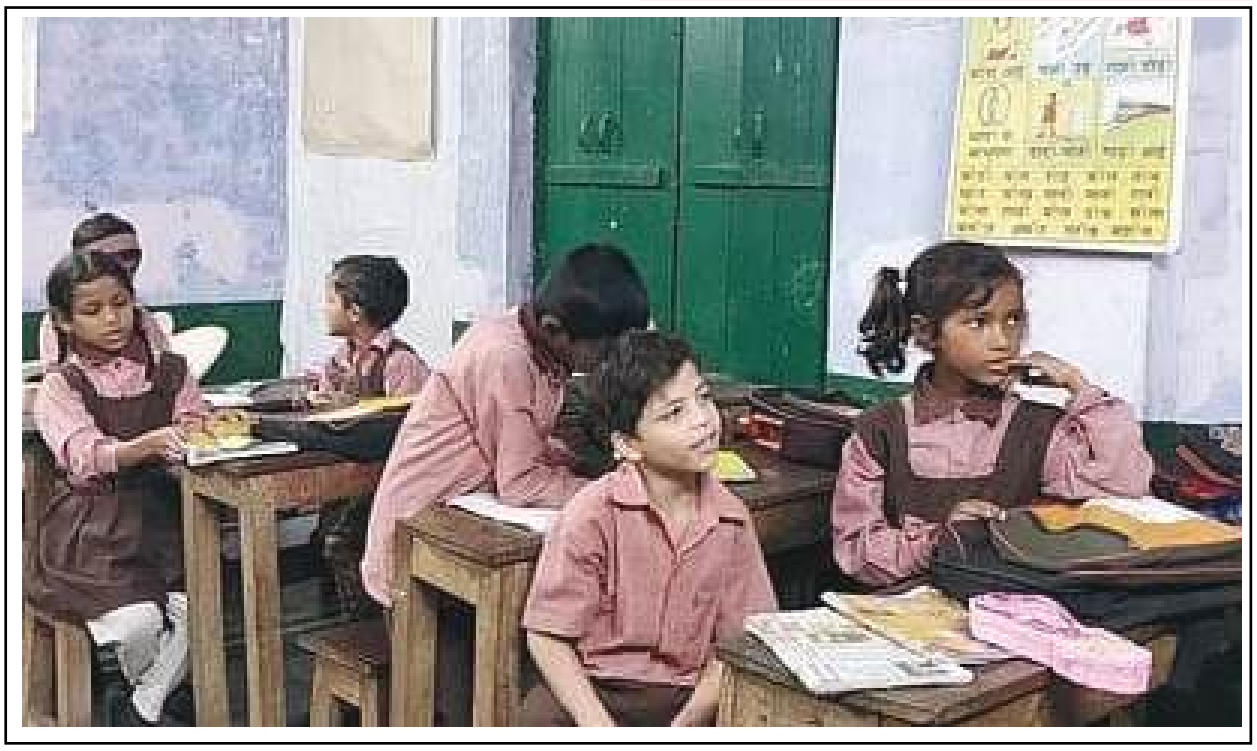

डीबीटी से हर साल वंचित रह जाते हैं लाखों बच्चे

बिल्हौर। यूं तो सरकार प्रत्येक बच्चे को डीबीटी की धनराशि देने का दावा करती है लेकिन हकीकत इससे कोसों दूर है। हकीकत में बच्चे, उसके माता और पिता का आधार सत्यापन पूरा होने के बाद ही यह रकम मिलती है। आंकड़ों के मुताबिक प्रतिवर्ष सरकारी अभिलेखों में मामूली भिन्नता के चलते लाखों बच्चे डीबीटी से वंचित रह जाते हैं। नामांकन में सख्ती कहीं थे रकम बचाने के लिए तो नहीं की गई है।

सूखी टोटियां, अधूरी टंकी...जल जीवन मिशन योजना का सच

पानी आने के इंतज़ार की तपिश में झुलसते डीग गांव के लोग

स्वराज इंडिया ब्यूरो

कानपुर देहात। मलासा ब्लॉक स्थित डीग गांव में पेयजल संकट गंभीर होता जा रहा है। जल जीवन मिशन के तहत गांव में पानी की टंकी का निर्माण 13 जनवरी 2023 को शुरू होना था, और 12 जनवरी 2024 तक इसे पूरा किया जाना था।

लेकिन डेढ़ साल बीत जाने के बावजूद अब तक टंकी अधूरी है और निर्माण कार्य ठप पड़ा है। 246.57 लाख रुपये की लागत से बनने वाली इस टंकी के अधूरे काम का खामियाजा गांववासियों को भुगतना पड़ रहा है। कुछ घरों में दिखावटी तौर पर टोटियां तो लग चुकी हैं, लेकिन उनमें पानी नहीं आता।

कई परिवारों को आज भी कागजों पर ही पानी की आपूर्ति दिखाई जा रही है।

गर्मी का मौसम शुरू होते ही समस्या और गंभीर हो गई है — लोग हैंडपंपों पर एक-एक बाल्टी पानी के लिए लाइन में खड़े हो रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि अधिकारियों से कई बार शिकायत करने के बावजूद कोई ठोस जवाब नहीं मिला। वे पूछते हैं — 'इन सूखी टोटियों में आखिर पानी कब आएगा'जल जीवन मिशन, जो कि केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, का उद्देश्य था हर ग्रामीण घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाना। वित्तीय वर्ष 2022-23 में इसके लिए 60,000 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया था। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि डीग गांव जैसे कई स्थानों पर यह योजना सिर्फ कागजों पर ही सफल दिखाई देती है। आज भी ग्रामीणों की उम्मीदें अधूरी टंकी और बंद पड़ी पाइप लाइनों में अटकी हुई हैं। अफसर चुप हैं और योजनाएं दम तोड़ रही हैं।

गर्मी का मौसम चल रहा है। इस समय पानी की किल्लत हर जगह हो रही है। लेकिन हमको अभी भी उम्मीद नहीं दिखा रही है कि इस साल भी टंकी नहीं बन पायेगी। अभी तक टोटी तो लगी हुई है लेकिन पानी का इंतजार कर रहे हैं।ओर विभाग में अपनी मनमानी चल रही है।

अंकित शुक्ला एडवोकेट

गांवों में हैंडपंप पर लोगों की भीड़ लगी रहती है। टंकी का निर्माण कार्य शुरू होने से उम्मीद जगी थी। लेकिन फिर हम वहीं मुसीबत से जूझ रहे हैं। रेलवे क्रॉसिंग की तरफ कुछ घरों में पानी की फोटो अफसरों को भेज दी जाती हैं। की पानी चल रहा है। हकीकत यह कि हम लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे। लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। **प्रदीप सिंह डीग निवासी**

गांव में हैंडपंप पानी देना बंद हो रहे हैं। गांव में रिबोर की जरूरत है। लेकिन गांव में डेढ़ साल से अधिक टंकी बन रही है। हमको आस जगी थी पानी की टंकी बन रही है। तो आराम हो जाएगी लेकिन सब अरमानों में पानी फेर गया है।

डीग गांव निवासी राम जी

पानी का दुःख हमसे पूछो हैंडपंप कितनी दूर लगा है। हमको अब उम्मीद नहीं है कि टंकी से हमको पानी मिलेगा। अभी भी हैंडपंप की शरण ले रहे हैं। कोई सुनने वाला नहीं है। हैंडपंप अब कम पानी दे रहे हैं। लेकिन पानी की टंकी नहीं बन रही है।

श्री राम डीग गांव निवासी

भोगनीपुर में तांत्रिक बना दरिंदा

स्वराज इंडिया ब्यूरो

कानपुर देहात। जनपद के भोगनीपुर कोतवाली क्षेत्र से एक संवेदनशील मामला सामने आया है, जहां एक किशोरी ने एक तांत्रिक पर यौन शोषण का आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। परिजनों के अनुसार, किशोरी का इलाज कराने के बहाने आरोपी उसे गांव के बाहर ले गया और तांत्रिक क्रिया के नाम पर उसके साथ गलत हरकतें की। परिवार की मानें तो यह घटना करीब दो महीने पहले हुई थी, लेकिन डर और धमकी के चलते पीड़िता चुप रही। बाद में उसने अपनी भाभी को घटना की जानकारी दी। परिजन जब इस मामले की शिकायत लेकर स्थानीय थाने पहुंचे, तो न तो एफआईआर दर्ज की गई और न ही पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया गया। इसके बाद परिवार ने

झूठे तंत्र के जाल में फंसी मासूम के साथ की हरकत, एसपी से की शिकायत

मामले को पुलिस अधीक्षक के संज्ञान में लाया।

पुलिस अधीक्षक ने दिए जांच के आदेश, कार्यप्रणाली पर उठे सवाल

पीड़िता की शिकायत पर एसपी कानपुर देहात अरविंद मिश्र ने तत्काल प्रभाव से जांच के निर्देश दिए हैं। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी और दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई होगी। इस घटना ने स्थानीय पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। यदि जांच में प्रथम दृष्टया लापरवाही सामने आती है, तो जिम्मेदार पुलिसकर्मियों पर भी विभागीय कार्रवाई संभव है।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक सपना देवी द्वारा हर्षिता प्रिंटर्स 127/875, साकेत नगर, कानपुर नगर- 208012 (उप्र) से मुद्रित व 119/13, दर्शनपुरवा, कानपुर नगर- 208012 (उप्र) से प्रकाशित। **संपादक:** अनूप कुमार **RNI No.:** UPHIN/2023/86769 | **Email:** swarajindia2023@gmail.com | **Mob:** 7800009853, | **Website:** www.swarajindianews.com | **प्रधान संपादक रतन प्रकाश सिंह (समस्त वाद-विवाद कानपुर न्यायालय के अधीन होंगे)**

वेंटीलेटर पर कई जीवनदायिनी एम्बुलेंस

स्वास्थ्य विभाग की 812 एंबुलेंस को निष्प्रयोज्य घोषित करते हुए नीलाम करने का आदेश हो चुका है, लेकिन चार माह से यह आदेश फाइलों के बीच दबा पड़ा

अंकित यादव स्वराज इंडिया

बाराबंकी। लोगो की जीवन रक्षा करने वाली एम्बुलेंस ही अगर वेंटीलेटर पर हो तो ऐसा सुन के आप चौंकिए मत, क्यूंकि ये सच है, जी हा, यूपी के बाराबंकी जनपद में मरीजों का लाने ले जाने वाली एम्बुलेंस ही अनफिट है, वही दूसरी तरफ फिटनेस न होने पर अन्य वाहनों पर कार्यवाही की बात की जाती है मगर सरकारी अमले में ही नियम की धज्जियां उड़ाई जा रही है।

चलिए आपको मामला विस्तार से समझाते हैं, दरअसल, प्रदेश की आपातकालीन स्वास्थ्य सेवा कंडम व अनफिट एंबुलेंस के सहारे चल रही है, जनपद में स्वास्थ्य विभाग की 812 एंबुलेंस को निष्प्रयोज्य घोषित करते हुए नीलाम करने का आदेश हो चुका है, लेकिन चार माह से यह आदेश फाइलों के बीच दबा पड़ा है। ऐसी सेवा से मरीजों की जान जोखिम में रहती है।

आपातकालीन सेवा देने वाली 108 एम्बुलेंस की करीब 1600 एबुलेंस सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय(आरटीओ) बाराबंकी में पंजीकृत हैं, जिसमें से अधिकांश की फिटनेस फेल है, बावजूद इसके वे मरीजों की सेवा में दौड़ रही हैं। अनफिट एम्बुलेंस में से 812 तो ऐसी हैं, जो कबाड़ (निष्प्रयोज्य) घोषित हो चुकी हैं। इनको नीलाम कर निस्तारण का आदेश दिसंबर 2024 में ही दिया जा चुका है, लेकिन संबंधित विभाग इसको लेकर गंभीर नहीं है।

108 एम्बुलेंस सेवा की 812 एंबुलेंस एवं उनमें स्थापित चिकित्सीय उपकरणों को निष्प्रयोज्य घोषित किए जाने के लिए परिवहन विभाग के शासनादेश व प्रविधान के तहत महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक ने नौ दिसंबर 2024 में यह निर्णय लिया था। इसके तहत 108 एम्बुलेंस सेवा में सम्मिलित 812 एम्बुलेंस और उसमें लगे चिकित्सीय उपकरणों को निष्प्रयोज्य घोषित करते हुए नीलाम किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी। इसके दृष्टिगत महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य ने प्रदेश के सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को पत्र जारी कर निर्देशित किया है कि 812 एंबुलेंस एवं उनमें लगे चिकित्सीय उपकरणों को यथाशीघ्र नीलाम करके निस्तारण किया जाए। नीलाम अथवा निस्तारण से प्राप्त होने वाली धनराशि को संबंधित मद में जमा कराने का भी आदेश दिया है। पूरे प्रदेश में जारी हुआ था पत्र नीलाम व निस्तारण का यह पत्र दूसरे दिन ही 10 दिसंबर 2024 को प्रदेश के महालेखाकार, प्रमुख सचिव, चिकित्सा, मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और परिवहन आयुक्त सहित सभी मंडलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,

बाराबंकी में अब उन्हीं अनफिट एम्बुलेंस से ढोए जा रहे मरीज

हालांकि इस मामले पर सीएमओ डा. अवधेश कुमार यादव ने बताया कि अनफिट व कंडम एंबुलेंस को नीलाम करने को लेकर कार्यवाही की जा रही है, वही इस पूरी व्यवस्था को लेकर आरटीओ अंकिता शुक्ला का कहना है इस मामले को लेकर निरंतर पत्राचार किया जा रहा है।

तेज रफ्तार बस ने छीनी तीन जिंदगियां...

» पुखरायां में दर्दनाक सड़क हादसा, परिजनों का हंगामा

स्वराज इंडिया ब्यूरो

कानपुर देहात। पुखरायां के पटेल चौक के पास शुक्रवार शाम एक भीषण सड़क हादसे में मोटरसाइकिल सवार तीन युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। तेज रफ्तार बस से हुई जोरदार टक्कर ने कमलजीत (30), अर्जुन (32) और अनुराग (28) की जिंदगी छीन ली। तीनों युवक मोटरसाइकिल से झांसी–कानपुर हाईवे पर कानपुर की ओर जा रहे थे, तभी सोम ढाबा के पास यह भीषण हादसा हुआ।हादसे की सूचना मिलते ही क्षेत्राधिकारी संजय कुमार सिंह, कोतवाल अंजन कुमार सिंह और चौकी प्रभारी जितेंद्र तिवारी घटनास्थल पर पहुंचे और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। घटना से आक्रोशित परिजनों ने हाईवे पर जाम लगा दिया और दोषी बस चालक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने सूझबूझ से स्थिति को नियंत्रित करते हुए जाम हटवाया और यातायात बहाल कराया।पटेल चौक और सोम ढाबा क्षेत्र में आए दिन हो रहे हादसों को लेकर क्षेत्रीय लोग प्रशासन से ठोस कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। कोतवाल अंजन कुमार सिंह ने बताया कि तहरीर मिलने पर संबंधित बस चालक के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी।

विप्र समागम में दंदरौआ सरकार ने ब्राह्मण समाज को दिखाया मार्ग

स्वराज इंडिया संवाददाता

कानपुर देहात। कस्बा अकबरपुर के जनकपुरी मैदान में शुक्रवार को भगवान परशुराम जन्मोत्सव पर जिला स्तरीय विप्र समागम हुआ। यहां संत पूजन, कथाव्यास व पुरोहितों का सम्मान, भजन प्रवाह, परशुराम संवाद हुआ। मुख्य अतिथि के तौर पर दंदरौआ सरकार महामंडलेश्वर संत रामदास जी महाराज शामिल हुए। उन्होंने इस दौरान कहा कि ब्राह्मण जनेऊ (यज्ञोपवीत) व सिर में शिखा (चोटी) जरूर धारण करें।आयोजक भार्गव परशुराम सेवा समिति के सदस्यों ने मुख्य अतिथि मध्यप्रदेश दंदरौआ धाम के महामंडलेश्वर संत रामदास जी महाराज व कार्यक्रम के अध्यक्ष रामजानकी आश्रम गौरियापुर के महंत देवनारायण दास का पूजन किया। इससे पहले मुख्य अतिथि दंदरौआ सरकार अकबरपुर चौराहे से खुली जीप में काफिले संग कार्यस्थल तक पहुंचे। जगह जगह समिति के लोगों ने पुष्प वर्षा की और आरती उतारी। विप्र समागम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि ने कहा किभगवान परशुराम विष्णु जी के छठवें औतार थे। इन्होंने

पृथ्वी लोक से आततायियों का संहार का मानव जाति का कल्याण किया। महंत देवनारायण दास जी महाराज ने कहा कि भगवान परशुराम के जीवन चरित्र और उनके आदर्शों को अपनाने की जरूरत है।प्रख्यात परशुराम अभिनेता जितेंद्र पांडेय, लक्ष्मण अभिनेता डॉ दीपकांत शुक्ल, भागवताचार्य महेंद्र मिश्रा पीयूष, पं. प्रदीप मिश्रा सहित करीब दो सौ आचार्यों, पुरोहितों, कर्मकांड परंपरा से जुड़े ब्राह्मणों का प्रतीक चिह्न भेंटकर सम्मान किया गया। ककवन के आशीष अवस्थी भगवान परशुराम के स्वरूप में मंच पर विराजमान रहे। गायक लालजी त्रिपाठी ने भजन प्रस्तुत किए। इस मौके पर लक्ष्मीकांत दीक्षित, ब्रह्मकुमार द्विवेदी, शिवशंकर शुक्ला, अवधेश तिवारी, मनोज त्रिवेदी, प्रदीप मिश्रा प्रधानाचार्य अर्पित मिश्रा, शिक्षाविद डॉ. नरेंद्र द्विवेदी, रविशशि द्विवेदी, नगर पंचायत अध्यक्ष राजपुर अंशु त्रिपाठी, कमलेश पांडेय, शरद शुक्ला, रामबाबू शुक्ला, प्रमोद शुक्ला, बालजी शुक्ला, आयुष त्रिवेदी गुड्डू मिश्रा, विपिन चंद्र दीक्षित,, अंकित अवस्थी आदि मौजूद रहे।

यूजीसी के दखल से बीएचयू प्रोफेसर महेश प्रसाद बने विभागाध्यक्ष

» बीएचयू कुलपति के सानिध्य में रजिस्ट्रार की मनमानी आई सामने तो यूजीसी ने दिए निर्देश

» वरिष्ठता के क्रम में प्रोफ़ेसर महेश प्रसाद को सौंपी गई विभागाध्यक्ष कुर्सी, छात्रों ने जताई खुशी

» आपके अपने अखबार स्वराज इण्डिया ने विश्वविद्यालय की अनियमित्ताओं को प्रमुखता से उजागर किया था

खास खबर

स्वराज इंडिया
अपना प्रदेश
बीएचयू में विभागाध्यक्ष पद को लेकर खींचतान
» बीएचयू के कुलपति के खिलाफ प्रदर्शन, मनमर्जी से नियमों और संवैधानिक व्यवस्था को दरकिनार किया
» विश्वविद्यालय में छिड़ा विरोध प्रदर्शन, अधर में नियुक्ति होने के बावजूद तृतीयवर को विभागाध्यक्ष पद देने पर भड़के
विश्वविद्यालय में अनियमितताओं के चल रहे 400 से अधिक मामले
कुलपति की सरपरस्ती में बीएचयू रजिस्ट्रार कर रहे खेल

स्वराज इंडिया
अपना प्रदेश
जिनको नियमों की जानकारी नहीं वे बीएचयू के कुलपति और रजिस्ट्रार
» यूजीसी ने दिखाया आईना तो बीएचयू कुलपति और रजिस्ट्रार की योग्यता पर उठ रहे सवाल
» नियमों को दरकिनार कर प्रोफ़ेसर की वरिष्ठता के सिलसिले में खुली कुलपति व् रजिस्ट्रार की पोल

प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

वाराणसी। सन्मार्ग के रास्ते पर गुरु और शिष्य साथ मिल कर चाह लें तो समाज में लोक कल्याण और न्याय का रास्ता प्रशस्त होने में देर नहीं लगती। काशी हिन्दू विश्वविद्यालय (बीएचयू) में यह उदाहरण सामने आया है। प्रोफ़ेसर ने जहाँ न्याय हित में अनियमित्ताओं और गड़बड़झाले के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया वहीं उनके छात्रों ने हकूक की आवाज़ बुलंद की और जिम्मेदारों को झकझोरा भी, परिणाम सामने आया, भ्रष्टाचार उजागर हुआ और हक़ की जीत हुई । उत्तर प्रदेश का बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय विश्वविख्यात है। देश दुनियां को विभिन्न क्षेत्रों के तमाम विद्वान् इस विश्वविद्यालय ने दिए हैं लेकिन शिक्षा के मंदिर में उच्च पदों पर बैठे कुछ जिम्मेदार मठाधीशों ने अपनी कुत्सित मानसिकता के विश्वविद्यालय की साख पर बट्टा लगाने का काम किया है। । बीएचयू के कुलसचिव प्रो. अरुण कुमार सिंह हैं और यहाँ के कुलपति प्रोफ़ेसर संजय कुमार हैं।

दरअसल बीएचयू में नियमों की अवहेलना करके एक सुनियोजित साजिश के तहत चहेतों को लाभ पहुँचाने के लिए सीनियरिटी को दरकिनार करके प्राचीन भारतीय इतिहास संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग में प्रोफेसर महेश प्रसाद को विभाग अध्यक्ष नहीं बनाया गया है। उनकी जगह विभाग अध्यक्ष की जिम्मेदारी कला संकाय प्रमुख को दे दी गई है। जबकि विश्वविद्यालय के कानून 25(4)2 का पालन में वरिष्ठता के साथ प्रोफेसर महेश प्रसाद की नियुक्ति विभाग अध्यक्ष के रूप में की जानी थी।

इस अहित को लेकर प्रोफ़ेसर महेश प्रसाद ने अपनी बात जिम्मेदारों तक रखी। न्याय हित में बीएचयू में मनमानी करके प्रशासनिक अराजकता फैलानेवाले रेक्टर और रजिस्ट्रार के खिलाफ छात्रों ने राष्ट्रपति, केंद्रीय शिक्षा मंत्री और यूजीसी को ईमेल पत्र भी भेजा। जिसके जवाब में यूजीसी के उप सचिव डा. निखिल कुमार ने बीएचयू के कुलसचिव को आयोग व मानव संसाधन विभाग मंत्रालय की नियमावली की ओर नोटिस कराते हुए विभागाध्यक्ष के विवादित मामले के निस्तारित करने के निर्देश दिए। आपको बताते चलें कि छात्रों के प्रवेश को लेकर भी लगातार गड़वड़ियाँ सामने आईं जिनपर छात्रों ने न्याय को लेकर आंदोलन तक किये हैं, और अपना वाजिब हक़ हासिल किया है। विश्वविद्यालय में यह एक दो प्रकरण नहीं है अनियमित्ताओं के सैकड़ों मामले न्याय की बाट जोहते अदालतों की चौखट पर दस्तक दे चुके हैं।

तत्काल जारी हुई पदस्थापना की अधिसूचना

यूजीसी से जारी निर्देश की प्रति जैसे ही रजिस्ट्रार दफ्तर में प्राप्त हुई तो तिकड़म रचने वालों के होश उड़ गए। यह यूजीसी का स्पष्ट निर्देश था। आनन फानन में मीटिंग का दौर चला और बिना देर करते हुए सहायक कुलसचिव ऐके शर्मा ने प्रोफ़ेसर महेश प्रसाद को विभागाध्यक्ष के रूप में पदस्थापना का नोटिफिकेशन जारी किया।

हर वह आदमी पत्रकार जो सच्चाई को बोलने का साहस रखता है...

(विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस विशेष)

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर । 1993 से हर साल 3 मई को मनाया जाने वाला विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस प्रेस स्वतंत्रता के सार्वभौमिक महत्व और लोकतंत्र, पारदर्शिता और मानवाधिकारों की रक्षा में पत्रकारिता की भूमिका की याद दिलाता है। विश्वभर में यह दिन मीडिया के योगदानों को याद करने के लिए समर्पित होता है। यह दिवस हमे मीडिया की आजादी के महत्व के बारे में बताता है और पत्रकारों की सुरक्षा के लिए आवाज उठाने के लिए प्रेरित भी करता है। पत्रकारिता अब केवल पेशेवरों की जिम्मेदारी नहीं रही बल्कि हर जागरूक नागरिक उस दायित्व को निभा रहा है।

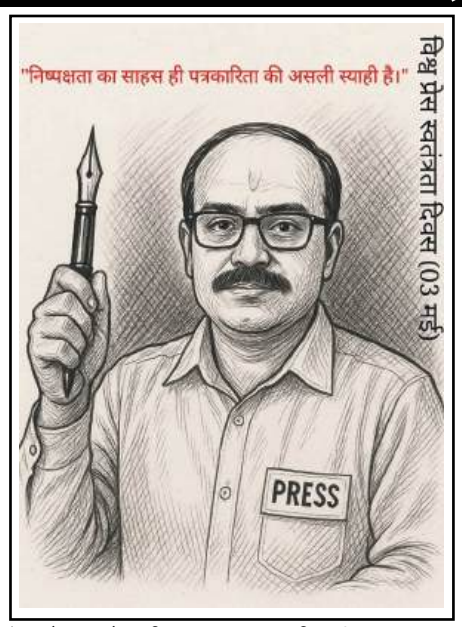

हर आम आदमी जो सच्चाई को पहचानता है, उसे बोलने का साहस रखता है और उसे दूसरों तक पहुँचाता है वह भी पत्रकार है। जब कोई किसी की बेबसी को वीडियो के माध्यम से सामने लाता है, जब कोई शासन, प्रशासन की अनदेखी को ट्वीट करता है या कोई अपनी बस्ती की समस्याओं को कैमरे में कैद कर दुनिया के सामने रखता है तो ये सारे काम पत्रकारिता के दायरे में आते हैं।

आज प्रेस की स्वतंत्रता केवल माइक और कैमरे वालों की स्वतंत्रता नहीं बल्कि उस हर व्यक्ति की स्वतंत्रता है जो अन्याय और असत्य के विरुद्ध खड़ा होता है।

पत्रकारिता अब रोजगार या पेशा नहीं बल्कि जमीर की जरूरत बन चुकी है। जब संस्थाएं कमजोर होती हैं, जब सत्ता सवालों से डरती है, तब वही आम नागरिक पत्रकार बनता है जो किसी अखबार या चैनल से नहीं जुड़ा होता लेकिन सच से जुड़ा होता है। हम ऐसे दौर में हैं जहाँ सच्चाई को दबाने की कोशिशें होती हैं, जहाँ सूचनाएं भी बिकती हैं और चुप्पी भी। ऐसे में जो लोग जोखिम उठाकर भी

अपनी आवाज को जन-जन तक पहुंचता है

निष्पक्षता से काम कर रहे हैं, वे ही सच्चे पत्रकार हैं, चाहे वे किसी न्यूज रूम में हों या किसी गली-कूचे में। ऐसे सभी पत्रकारों को हम सलाम करते हैं जो ना बिकते हैं, ना झुकते हैं और ना ही रुकते हैं। वे जो किसी दल या दबाव के नहीं, केवल लोकतंत्र और समाज के प्रति जवाबदेह हैं। अगर सच बोलने वाले चुप हो गए तो झूठ बोलने वाले हर जगह सत्ता संभाल लेंगे। हर हाथ में आज मोबाइल है, हर जेब में कलम है और हर मन में सवाल है बस जरूरत है उन्हें पूछने, लिखने और साझा करने की आजादी की। जब एक आम व्यक्ति पेन उठाता है तो वह भी उतना ही जरूरी हो जाता है जितना कि कोई नामी पत्रकार इसलिए आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस पर हम केवल मीडिया हाउस के पत्रकारों को नहीं बल्कि उस हर व्यक्ति को शुभकामनाएँ देते हैं जो सच्चाई के लिए लिख रहा है, बोल रहा है, खड़ा हो रहा है। हर पत्रकार को और हर उस आम आदमी को सलाम जिसके भीतर एक पत्रकार है।

भारत में प्रेस की स्वतंत्रता-

भारत में प्रेस की स्वतंत्रता का एक समृद्ध इतिहास रहा है हालांकि हाल के वर्षों में पत्रकारों को डराने-धमकाने और गिरफ्तार करने की घटनाए बढ़ी हैं। भारत में प्रेस की स्वतंत्रता की रैंकिंग भी पिछले कुछ वर्षों में गिरी है। भारत में पत्रकारों को काम करते समय कई शारीरिक खतरों और सुरक्षा चिंताओं का सामना करना पड़ता है। संवेदनशील मुद्दों पर रिपोर्टिंग करना, भ्रष्टाचार को उजागर करना और सत्ता में बैठे लोगों से निडर होकर सवाल करना उन्हें धमकियों, हिंसा या उत्पीड़न के खतरे में धकेल रहा है। निर्भीक पत्रकारिता करने वालों को समय-समय पर धमकियां मिलती रहती हैं। ये धमकियां राजनीति से अधिक प्रेरित हैं और ये रेत और भूमाफिया से आती हैं।

पत्रकारों को कभी-कभी अपनी रिपोर्टिंग को विशिष्ट एजेंडे के साथ जोड़ने के दबाव का सामना करना पड़ता है जिससे निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ कवरेज प्रदान करने की उनकी क्षमता प्रभावित होती है। पत्रकारिता की अखंडता बनाए रखने और जीवंत लोकतंत्र बनाए रखने के लिए पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण हो गया है।

स्वीकार नहीं होगी कानून-व्यवस्था में लापरवाही: डीआईजी केशव चौधरी

प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

ललितपुर। डीआईजी केशव कुमार चौधरी ने शुक्रवार को जनपद ललितपुर पहुंचे जहां पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुश्ताक ने बुके देकर स्वागत किया, वही सम्मान गार्द ने डीआईजी को गार्द सलामी दी।इसके बाद डीआईजी केशव कुमार चौधरी द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन्स में बने नवनिर्मित जिम का फीता काटकर शुभारंभ किया तथा उसमें रखें उपकरणों व सामान आदि का उन्होंने निरीक्षण किया।

» श्री चौधरी द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन्स में बने नवनिर्मित जिम का फीता काटकर शुभारंभ किया

» समीक्षा बैठक में कई सख्त निर्देश दिए गए

रिजर्व पुलिस लाइन्स के सभागार में आयोजित जनपदीय अपराध एवं कानून-व्यवस्था के सम्बन्ध में समीक्षा बैठक में सभी राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों व शाखा प्रभारियों को वांछित आरोपियों की गिरफ्तारी तथा लम्बित अभियोगों की विवेचना के निस्तारण के लिए विशेष अभियान चलाने,महिला संबंधी अपराध जैसे दुष्कर्म,शीलभंग,अपहरण,आदि के मामलों में त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रभावी निरोधात्मक कार्रवाई करने साथ ही अवैध शराब पर अंकुश लगाने के सख्त निर्देश दिए है।इस दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए है।

जिसमें मामलों की प्रगति की समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश जारी किए गए।साथ ही विवेचनाओं को अनावश्यक रूप से लंबित रखने वालों को कड़ी चेतवानी दी गई और समय सीमा के भीतर निष्पक्ष निस्तारण सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया।वहीं विवेचनाओं में भौतिक और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को शामिल करते हुए गुणवत्तापूर्ण जांच पर जोर दिया गया।इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पुरस्कार घोषित अपराधियों की गिरफ्तारी और गैंगस्टर एक्ट में चिन्हित आरोपितों की संपति जप्त की जाए।गोवध निवारण अधिनियम के आरोपितों पर गैंगस्टर आदि की कार्रवाई करें। जघन्य अपराधों व संपति संबधी अपराधों में संलिप्त अपराधियों की हिस्ट्रीशीट खोलकर निगरानी की जाए।बैठक में एसपी मोहम्मद मुश्ताक,एएसपी अनिल कुमार,सीओ सदर अजय कुमार,सीओ तालबेहट अभय नारायण राय,सीओ महरौनी रक्षपाल सिंह सहित सभी थाना प्रभारी व अन्य मौजूद रहे ।

रोड कटिंग के लिए विभागों को लेनी होगी ऑनलाइन परमिशन

» पोर्टल का फाइनल ड्राई रन शुक्रवार को जिलाधिकारी विशाख जी के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट सभागार लखनऊ में हुआ

प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

लखनऊ। शहरी क्षेत्रों में बिना समन्वय के की जा रही सड़क कटिंग और इससे होने वाले यातायात अवरोधों को रोकने के लिए लखनऊ प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। अब रोड कटिंग के लिए विभागों को ऑनलाइन परमिशन लेनी होगी। इसके लिए विकसित किए गए ऑनलाइन रोड कटिंग परमिशन सिस्टम (ORCPS) पोर्टल का फाइनल ड्राई रन शुक्रवार को जिलाधिकारी विशाख जी के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट सभागार में सम्पन्न हुआ।

यह पोर्टल आगामी 7 मई को GO LIVE कर दिया जाएगा, जिसके बाद बिना पोर्टल के अनुमति कोई भी विभाग या संस्था सड़क कटिंग नहीं कर सकेगी। बैठक में नगर निगम, जलकल, लोक निर्माण विभाग, विद्युत विभाग, एनएचएआई और सेतु निगम सहित अन्य विभागों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। डीएम ने स्पष्ट निर्देश दिए कि लेसा को भी पोर्टल में जोड़ते हुए चारों जोनों के लिए नोडल अधिशासी अभियंता नामित किए जाएं, ताकि भूमिगत केबिल की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

डीएम विशाख जी ने बताया कि पोर्टल पर आवेदन करने के बाद सात दिनों में निस्तारण किया जाएगा, यदि तय समयसीमा में अनापत्ति नहीं दी जाती है, तो ऑटो अप्रूवल मोड के तहत आवेदन स्वतः अग्रसारित हो जाएगा। उन्होंने बताया कि जलकल और विद्युत विभाग को आपातकालीन परिस्थितियों में कार्य हेतु 'इमरजेंसी एथोराइजेशन' का विकल्प भी पोर्टल में दिया गया है।शहरी क्षेत्रों की मेन रोड्स पर किसी भी तरह की कटिंग से पहले पोर्टल के माध्यम से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। डीएम ने कहा कि इस डिजिटल प्रणाली से विभागीय समन्वय में पारदर्शिता और गति आएगी, जिससे न सिर्फ सड़क सुरक्षा बढ़ेगी, बल्कि यातायात व्यवस्था भी सुचारु होगी।नोडल अधिकारी अपर जिलाधिकारी नगर पूर्वी अमित कुमार होंगे, जो पूरे सिस्टम की निगरानी करेंगे।आवेदनकर्ता को पोर्टल पर अधिकारी का नाम, मोबाइल नंबर, प्रस्तावित कार्य की समयसीमा, लोकेशन के जीपीएस कोऑर्डिनेट्स सहित अन्य तकनीकी जानकारियां दर्ज करनी होंगी।आवेदन संबंधित विभाग और ट्रैफिक पुलिस को स्वतः अग्रसारित होगा। विभाग स्थलीय निरीक्षण कर अपनी अनापत्ति देंगे। यदि सड़क मरम्मत हेतु धनराशि देय है तो जमा राशि के बाद ही अनुमति जारी की जाएगी।

लखनऊः मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को दिए निर्देश

अविवादित विरासत के मामलों का पंद्रह दिन में हो निस्तारण

» वरिष्ठ संवाददाता, स्वराज इंडिया ब्यूरो।

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को अधिकारियों को निर्देश दिये कि अविवादित विरासत के मामलों का निस्तारण अधिकतम 15 कार्यदिवस के भीतर किया जाए। राजस्व विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में शनिवार को मुख्यमंत्री ने दो महत्वपूर्ण बिंदुओं 'राजस्व वादों के समयबद्ध निस्तारण और भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण' को सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखते हुए स्पष्ट निर्देश दिए कि इन कार्यों को प्रत्येक स्तर पर तीव्र गति से पूरा किया जाए।

उन्होंने कहा कि भूमि संबंधी विवादों का शीघ्र समाधान न केवल जनविश्वास, बल्कि राज्य में निवेश और विकास के लिए भी आवश्यक है, वहीं लैंड रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण पारदर्शी, भ्रष्टाचार-मुक्त और उत्तरदायी शासन प्रणाली की नींव है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि शेष भू-अभिलेखों का डिजिटलीकरण शीघ्र पूर्ण किया जाए और शहरी क्षेत्रों का लैंड रिकॉर्ड तैयार कर उसे प्राथमिकता से ऑनलाइन पोर्टल पर सार्वजनिक किया जाए।

उन्होंने राजस्व परिषद के पोर्टल की रीडिजाइनिंग की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि यह अधिक उपयोगकर्ता अनुकूल और परिणाममूलक होना चाहिए। साथ ही लेखपाल से लेकर आयुक्त स्तर तक एकीकृत डैशबोर्ड विकसित करने का निर्देश दिया, ताकि विभागीय निगरानी सरल हो सके और आमजन को सीधा लाभ मिले।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्राधिकरणों के लैंडयूज डेटा को खतौनी पर प्रदर्शित किया जाए और धारा 80 के अंतर्गत भू-उपयोग परिवर्तन प्रक्रिया को सरल व पारदर्शी बनाया जाए। नामांतरण वादों को पूर्णतः ऑटोमेट किए जाने की आवश्यकता को रेखांकित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे नागरिकों को सुगमता और समयबद्ध न्याय प्राप्त होगा।

उन्होंने चकबंदी प्रक्रिया में तकनीकी हस्तक्षेप और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, साथ ही सावधान किया कि चकबंदी की जटिलताओं के कारण गंभीर सामाजिक विवाद जन्म ले सकते हैं, अतः इसे अत्यंत संवेदनशीलता से निपटाया जाए। योगी ने यह भी स्पष्ट किया कि रियल टाइम खतौनी, आधार सीडिंग, किसान रजिस्ट्री, पैमाइश और खसरा पड़ताल से जुड़े सभी लंबित प्रकरणों का समाधान तय समय सीमा में अनिवार्य रूप से किया जाए।

इसके लिए आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त मानव संसाधन की व्यवस्था की जाए। विभाग द्वारा प्रस्तुत जानकारी के अनुसार, विगत वर्ष में ही 36 लाख से अधिक जाति, निवास एवं आय प्रमाण पत्र निर्गत किए गए, जिनमें से 85 प्रतिशत आवेदन सात कार्यदिवसों के भीतर ऑनलाइन निस्तारित हुए। मुख्यमंत्री ने इस प्रगति को सराहनीय बताया और सेवा वितरण को और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाए जाने के निर्देश दिए।

प्राकृतिक आपदा की स्थिति में त्वरित सहायता के लिए मुख्यमंत्री ने विभाग की सराहना करते हुए बताया कि वर्ष 2023-24 में 3.5 लाख से अधिक प्रभावित परिवारों को डीबीटी के माध्यम से सहायता राशि उपलब्ध कराई गई। उन्होंने निर्देशित किया कि मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के सभी लंबित आवेदन अगले 10 कार्यदिवसों में पूर्ण रूप से निस्तारित किए जाएं।

फेशियल अटेंडेंस का पालन न करने पर कार्रवाई

दो हजार से ज्यादा कर्मियों का वेतन रुका

» वरिष्ठ संवाददाता, स्वराज इंडिया ब्यूरो।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में बिजली कर्मियों को विभाग ने ही करारा झटका दिया है। फेशियल अटेंडेंस की अनिवार्यता का पालन न करने वाले 2000 से ज्यादा बिजली कर्मियों का अप्रैल का वेतन रोकने का आदेश मध्यांचल विद्युत वितरण निगम ने जारी किया है। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने इस आदेश पर आपत्ति दर्ज जतायी है। वहीं, शुक्रवार से निजीकरण के खिलाफ बिजली कर्मचारियों का क्रमिक अनशन शक्ति भवन पर शुरु हो गया।

संघर्ष समिति के संयोजक शैलेंद्र दुबे के मुताबिक, संविदा कर्मचारियों की बड़े पैमाने पर छंटनी चल रही है। इसके अलावा 2000 से ज्यादा बिजली कर्मचारियों का वेतन रोके जाने के भी आदेश भी जारी हो गया है, जिससे कर्मचारियों में नाराजगी है। उन्होंने आदेश को तानाशाहीपूर्ण बताते हुए हटाए गए सभी संविदा कर्मचारियों को फिर से नौकरी में लिए जाने और वेतन के भुगतान करने की मांग की है।

शैलेंद्र दुबे ने कहा कि मौजूदा निदेशक (वि) निधि कुमार नारंग को सलाहकार बनाकर सेवा विस्तार दिया जाना अनुचित है। उन्होंने आरापे लगाया कि, निजीकरण की आड़ में होने वाले भ्रष्टाचार में वह मुख्य कड़ी हैं। शैलेन्द्र दुबे ने जानकारी दी कि शनिवार लखनऊ में बाइक रैली निकाली जाएगी।

शर्मनाकः निकाह से पहले बहन से किया बलात्कार

शिकायत पर मां ने डांटा, ससुराल वालों ने दर्ज कराया केस

कलयुगी भाई

» लखनऊ, स्वराज इंडिया ब्यूरो।

यूपी राजधानी लखनऊ के पारा इलाके में बहन के निकाह के पहले भाई ने उसके साथ दो बार दुष्कर्म किया। शिकायत पर माता-पिता ने बेटी को ही डांटकर चुप करा दिया। ससुराल पहुंचने हालत बिगड़ने पर डॉक्टर को दिखाया तब गर्भवती होने की जानकारी हुई।

ससुरालवालों ने साथ देने की बात की, तब पीड़िता ने पारा थाने में भाई के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। इंस्पेक्टर सुरेश सिंह ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। थाना क्षेत्र की युवती का निकाह कई महीने पहले तय हो गया था। 15 अप्रैल को निकाह हुआ। निकाह के कुछ दिन बाद युवती की तबीयत खराब रहने लगी। ससुरालवालों ने 29 अप्रैल को मेडिकल चेकअप कराया तो डॉक्टर ने गर्भवती होने की जानकारी दी।

ससुरालवालों ने घर पहुंचकर बहू से बात की, लेकिन डर के चलते वह खामोश रही। समझा-बुझाकर पूछा तब बताया कि घिनौनी हरकत सगे भाई ने की है। पीड़िता ने बताया कि 1 अप्रैल को वह सोने के लिए जा रही थी। भाई कमरे में घुस आया और अश्लील हरकतें करने लगा। विरोध पर बंधक बनाकर दुष्कर्म किया। पीड़िता ने शोर मचाने का प्रयास किया तो मुंह दबा दिया। बोला कि 15 अप्रैल को तुम्हारी शादी है। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। किसी को कुछ भी बताने पर भाई ने जान से मारने की धमकी दी।

पहले भी किया था रेप

पीड़िता ने बताया कि भाई ने उसके साथ तीन महीने पहले भी गलत काम किया था। विरोध करने पर उसकी पिटाई कर दी थी। थाने में रोते हुए पीड़िता ने पुलिस को बताया कि भाई की हरकत माता-पिता को बताई थी तो उन लोगों ने उसे ही डांट कर शांत करा दिया था।

दहेज में फंसाने की दी धमकी

पीड़िता ने पुलिस को बताया कि सच सामने आने के बाद ससुरालवालों ने उसके माता-पिता से बात की। आरोपी भाई के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा। इस पर आरोपी के माता-पिता ने उल्टा उन्हें ही शांत रहने की धमकी दे डाली। शांत न रहने पर दहेज प्रताड़ना के आरोप में फंसाने की धमकी दी।